संकल्पना नोट

भारत की जी–20 की अध्यक्षता इस बंटी हुई दुनिया में सामंजस्य कायम होने के अपार अवसरों का भरोसा दिलाती है। हाल के वर्षों में विश्व ने गहन संकट का सामना किया है। जी–20 के लिए सांत्वनापूर्ण, सद्भाव और उम्मीदों से भरपूर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश भारत की जी–20 की अध्यक्षता की गतिविधियों और डिलिवरेबल्स को आकार देगा। भारत जी–20 के लिए एक ऐसे एजेंडे को अपनाने के लिए तत्पर है, जो समूची मानवता को लाभान्वित करने हेतु मूलभूत मानसिकता में बदलाव लाने में सक्षम परिस्थितियों का निर्माण करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया है। वैश्विक सुशासन संबंधी दृष्टिकोणों को अब से मौजूदा चुनौतियों को ''एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य'' की भावना में सार्वभौमिक और अविभाज्य के रूप में देखना चाहिए। इस विचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब ''पर्यावरण सम्मत जीवन शैली– LiFE'' के रूप में भी परिलक्षित होता है, जो व्यक्तियों से लेकर संस्थानों तक विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन का आह्वान करता है। संभवतः यह मौलिक रूप से

मूल्यों और नैतिक दृष्टिकोण से संबद्ध है, जिसे संस्थानों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार लाने के लिए मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है। हालांकि, वैश्विक सुशासन और संस्थाओं के लिए परिवर्तनों के साथ–साथ नैतिक मूल्यों और सुमंगलम के उदात्त विचार प्रदान करने के लिए साधनों, अवधारणाओं, साक्ष्यों, रोडमैप और साझेदारियों की व्यापक स्वीकृति होनी चाहिए। इससे संसाधनों का संवर्द्धित और तर्कसंगत आवंटन; विकास का स्थानीयकरण; प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहुंच, इक्विटी और समावेशन लाना; और विकास संबंधी साझेदारियों, व्यापारिक संबंधों और क्षमता निर्माण का नए सिरे से निरुपण किया जा सकेगा। ये पर्यावरण सम्मत जीवनशैली–LiFE, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलम युक्त वैश्विक सुशासन हासिल करने और संरचना, वित्त तथा तकनीक में सहयोग का संचार करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

LiFE को अपनाना, मूल्य और वित्त प्रदान करना

मानवता ने अपार प्रगति हासिल की है, जिससे अधिकांश लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, हिंसा में कमी आई है और लोगों की परस्पर बातचीत में शिष्टता बढ़ी है। इसके बावजूद, मानवता अपनी अत्यधिक उन्नत प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और प्रशासनिक क्षमताओं से उतना हासिल नहीं कर सकी है, जो वह हासिल कर सकती थी। हम सामूहिक विनाश की क्षमता वाले हथियारों से तबाही के खतरे से नहीं उबर पाए हैं। हमने विकट गरीबी का उन्मूलन नहीं किया है, दुनिया के लगभग आधे इंसान अभी तक स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हैं। हम मानवीय गतिविधियों को इस ग्रह को जीवन के अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप ढाल पाने में विफल रहे हैं। साथ ही हम सभी के हितों का ध्यान रखने वाली तथा असमानताओं और शोषण में कमी लाने वाली वैश्विक सुशासन संस्थाएं हासिल नहीं कर सके हैं। इतना ही नहीं, 'मानव–केंद्रित' विकास की रणनीति ने अन्य प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है और हमारे ग्रह से अनेक प्रजातियों का वजूद ही मिट गया है। महान नैतिक कार्यों को पूर्ण किया जाना अभी बाकी है – और असल खतरा इस बात का है कि यदि हमने सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित प्रणालियों और संस्थाओं की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की, तो अतीत में मानव जीवन की बेहतरी के लिए हासिल किए गए कुछ लाभों

का रुख पलट जाएगा। इसलिए LiFE को अपनाया जाना, गहराई से मूल्य प्रणालियों और नैतिक दृष्टिकोणों से जुड़ा है। इस बात पर गौर करना होगा कि LiFE और जिम्मेदारी से उपभोग का रास्ता अपनाने में सहायता करने के लिए वित्तीय प्रणालियों को किस तरह अनुकूलित किया जा सकता है। अंत में, हमें वित्तीय प्रणालियों में संपूर्णता लाने के लिए मूल्य आधारित दृष्टिकोण और नैतिक मानदंड स्थापित करने, शासन की संरचना को प्रौद्योगिकी के दायरे में विस्तारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के उद्भव के साथ नई वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है।

लचीले बुनियादी ढांचे, टिकाऊ शहर और टिकाऊ परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (आईएफआई) में सुधार के साथ–साथ बढ़ी हुई प्रतिबद्धताओं और नई साझेदारियों/उपकरणों के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने की दिशा में जी–20 को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर विकासशील और उभरते बाजारों में उच्च आवंटन की मांग करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना, गतिशीलता, सामाजिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना इत्यादि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जहां भी निवेश की आवश्यकता है, वर्तमान में उसका स्तर आदर्श से काफी कम है। आर्थिक मंदी ने व्यापक वित्तीय प्रवाह की संभावनाओं को और भी कम कर दिया है और कई अवसरों पर देश आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए अवसंरचना पर खर्च करने की स्थिति में नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, तकनीकी बदलावों और पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ लचीले बुनियादी ढांचे और टिकाऊ शहरीकरण की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है। इसी तरह, जैसा कि स्पष्ट है कि जलवायु वित्त के संबंध में नई प्रतिबद्धताएं पूरी होती प्रतीत नहीं हो रही हैं और वित्त के अभाव के कारण टिकाऊ परिवर्तन वास्तविकता के बजाय मिथक बने हुए हैं। एसडीजी और जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस स्थिति के गंभीर निहितार्थ हैं।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास तथा बच्चों और युवाओं में निवेश के जरिए एसडीजी हासिल करने में तेजी लाना

भारत ने अपनी जी–20 की अध्यक्षता के अंतर्गत एसडीजी हासिल करने में तेजी लाने को एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री ने भी युवाओं पर जोर देने का आह्वान किया है और विकास के लिए भारत की ओर से की गई पहलों ने यह प्रदर्शित किया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके और सामाजिक क्षेत्र के परिणामों में मात्रा के स्थान पर गुणवत्ता का रुख करने से सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव लाना संभव है। महिला सशक्तिकरण केवल उसी सूरत में हासिल किया जा सकता है जब वे आर्थिक और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। वित्तीय और डिजिटल समावेशन के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण के जरिये महिला सशक्तिकरण और निर्णय लेने में उनका प्रभावी प्रतिनिधित्व भारत सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसका दायरा बढ़ाते हुए ग्रामीण भारत में महिलाओं को उद्यमिता विकास के लिए व्यापक सहायता दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सामाजिक लचीलापन उत्पन्न हुआ है। अंत में, परिवर्तन का प्रमुख एजेंडा, जो एसडीजी के संबंध में कार्रवाई के एजेंडे को समेकित कर सकता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में निवेश और सामाजिक इक्विटी और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करने से संबद्ध है। किसी देश की मानव पूंजी का निर्माण और विकास मुख्य रूप से बच्चों को उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जहां तक संभव हो सर्वोत्तम पोषण, शिक्षा और आरोग्य प्रदान करने पर निर्भर करता है।

वन हेल्थ, वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा

उभरते रोगाणुओं से होने वाली महामारी के खतरों के साथ–साथ सूक्ष्मजीवीरोधी प्रतिरोध (एएमआर) की खामोशी से दस्तक देने वाली महामारी जारी है। हर साल अनुमानतः 700,000 लोगों की मृत्यु दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण हो जाती है। संचालकों या ड्राइवर्स की जटिलता, पशु, मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ

जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए देश वन हेल्थ के सिद्धांतों के आधार पर बहु–क्षेत्रीय, सहयोगपूर्ण, अंतर्विषयक दृष्टिकोण विकसित करते आ रहे हैं। इनमें जैव सुरक्षा उपाय, सूक्ष्मजीवीरोधी के विकल्प और पशु चारे के विकल्प शामिल हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए यदि वन हेल्थ फ्रेमवर्क में पारंपरिक हर्बल दवाओं को अपनाया जाए, तो उनका प्रमाणित प्रभाव महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है। जी–20 देशों को गैर संचारी रोगों–एनसीडी से उच्च मृत्यु दर (जी–20 में 70 प्रतिशत) और मानसिक रोगों से जुड़ी सह–रुग्णता का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) सेवाओं तक उचित पहुंच को बेहतर बनाते हुए इन चुनौतियों से संभावित रूप से निपटा जा सकता है और 2018 में अस्ताना घोषणा जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर, समकालीन वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए संकीर्ण महामारी विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक हर्बल दवाओं से प्राप्त टिकाऊ स्वास्थ्य रणनीति के रूप में कल्याण पर आधारित समग्र दृष्टिकोण की नितांत आवश्यकता है।

जीडीपी से आगे बढ़ते हुए : व्यवस्थाओं में बदलाव और सुमंगलम का आकलन

यह बड़े पैमाने पर महसूस किया जाने लगा है कि औद्योगीकरण की नई लहर और उत्पादन प्रणालियों के बदलावों को पर्यावरण के अनुकूल औद्योगीकरण और सभी क्षेत्रों में कार्बन और मैटिरियल फुटप्रिंट कम करने से संबद्ध प्रक्रियाओं पर केंद्रित होना चाहिए। व्यवस्थित दृष्टिकोणों के संदर्भ में, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में आम तौर पर तीन–क्षेत्रीय प्रणालियां– अर्थात सार्वजनिक, निजी और तृतीय क्षेत्र (यानी सरकार, लाभकारी व्यवसाय और गैर–लाभकारी संगठन) प्रचलित पायी जाती हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती चिंताओं के साथ, अनेक 'लाभकारी' कंपनियों ने सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने उद्देश्य को व्यापक बनाया है, जिससे अर्थव्यवस्था के 'चौथे क्षेत्र' का उदय हुआ है। वैश्विक चुनौतियों से

निपटने और अधिक समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए चौथा क्षेत्र आवश्यक माना जाता है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए मजबूत सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव प्रदान करने वाले दुनिया भर के उद्यमों में खरबों डॉलर की निजी पूंजी लगाई जानी चाहिए। हालांकि, चौथा क्षेत्र का इकोसिस्टम अभी तक नवोदित और अत्यधिक बंटा हुआ है। दूसरी ओर विश्व, विकास के परिणामों का बेहतर ढंग से आकलन करने और उत्तरोत्तर चुनौतीपूर्ण दुनिया में नीतिगत कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए विकास के जटिल आयामों पर विचार करने की आवश्यकता का सामना कर रहा है। जी–20 देशों सहित अनेक देशों ने बहुआयामी मेट्रिक्स विकसित किए हैं। हमें जी–20 सुमंगलम मेट्रिक्स को प्रतिपादित करने के लिए विकल्पों और व्यवहार्यता का आकलन करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में बेहतर अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और संसाधनों के आवंटन में सहायता करने के लिए किया जा सकता है।

एसडीजी के स्थानीयकरण में त्रिकोणीय सहयोग की भूमिका

त्रिकोणीय सहयोग एक परिवर्तनकारी साधन है, जो तेजी से बदलती विकास संबंधी चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी और लचीले समाधान प्रदान करता है। यह एक ऐसा तंत्र साबित हुआ है, जिसमें निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी, परोपकार, शिक्षा और राज्येतर कारक यानी सब–स्टेट एक्टर्स सहित मौजूदा दौर के विकास संबंधी विविध हितधारक शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ब्यूनस आयर्स में बीएपीए+40 सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की कि त्रिकोणीय सहयोग 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में योगदान देता है। परिणाम दस्तावेज़ (बीएपीए+40, अनुच्छेद–12) भी दक्षिण–दक्षिण सहयोग के पूरक प्रयास के रूप में त्रिकोणीय सहयोग को मान्यता देता है। यह त्रिकोणीय सहयोग की ''संसाधनों, विशेषज्ञता और क्षमताओं की व्यापक रेंज'' प्रदान करने की क्षमता को पहचानता है, जो विकास पथ पर विकासशील देशों की सहायता तथा राष्ट्रीय विकास हेतु और उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग से प्रेरित है। त्रिकोणीय सहयोग एक क्रियाशील

अवधारणा है, जो लगातार विकसित हो रही है। यह अब केवल ओईसीडी डीएसी सदस्यों और विकासशील देशों के बीच साझेदारी मात्र नहीं है।

व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं में नई पूरकताएं

व्यापार संबंधी संरक्षणवाद के साफ संकेत महामारी से पूर्व ही दृष्टिगोचर हो गए थे और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर काफी तनाव रहा है। वर्ष 2019 में कोविड से पहले के दौर में दुनिया का औसत ट्रेड ओपननेस इंडेक्स 55.45 प्रतिशत था, जो 2020 में घटकर 44.86 प्रतिशत हो गया और विकसित देशों का यह इंडेक्स, 2019 में 53.38 प्रतिशत से, विकासशील देशों की तुलना में काफी तेजी से घटकर 2020 में 39.28 प्रतिशत हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था के देशवार अनुभवों से संकेत मिलता है कि वैश्विक व्यापार का 50 प्रतिशत से अधिक वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं –जीवीसी और प्रौद्योगिकी गहन व्यापार द्वारा अलग से कवर किया जाता है, लेकिन वे पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं। इसलिए, इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दो सूचियों में कुछ उत्पाद सामान्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले तीस वर्षों में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में हुई तकनीकी प्रगति ने इस बात को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है कि डिजिटल बाजारों और प्लेटफार्मों के विकास का समर्थन करके वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का किस प्रकार क्रय, विक्रय और आदान–प्रदान किया जाता है (डब्ल्यूटीओ, 2021)। जी–20 बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बनाए रखने और साथ ही साथ मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से व्यापार में भाग लेने के लिए देशों के बीच व्यापक क्षमता का सृजन करने की दिशा में प्रयासरत है। हालांकि, बाजार तक पहुंच और व्यापार के वितरण संबंधी परिणामों में कठिनाइयां निरंतर बरकरार हैं, जो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के कारण और बढ़ गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन और औद्योगिक क्षमताओं के बारे में आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। इसके लिए व्यापार और मूल्य श्रृंखलाओं में नई पूरकताएं बनाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन और भागीदारी के बारे में

थिंक 20 (टी–20) जी–20 के कार्य समूहों में से एक है, जिसे 2012 में मैक्सिको की जी–20 की अध्यक्षता के दौरान आरंभ किया गया था। यह जी–20 के 'विचार बैंक' के रूप में कार्य करता है, जो महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के बारे में विद्वानों को विचार–विमर्श करने और नीतिगत सिफारिशें व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। भारत की टी–20 प्रक्रिया के अंतर्गत आरआईएस द्वारा 16–17 जनवरी 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में ''पर्यावरण सम्मत जीवनशैली (LiFE), नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमयुक्त वैश्विक सुशासन : संरचना, वित्त और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग का संचार'' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह टी–20 कार्यबल के सदस्यों, विषय के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, राजनयिकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठानों और सिविल सोसायटी (अन्य कार्य समूहों के सदस्यों सहित) को एक साथ लाकर टी–20 विमर्श को पूर्णता प्रदान करेगा।